



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 1984/पौष 28, 1905

No. 20]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 1984/PAUSA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेशी कर प्रभाग)

अधिसूचना:

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1984

आय-कर

सा० का० नि० 39(अ).—भारत गणराज्य की सरकार और जाम्बिया गणराज्य की सरकार के बीच, दोहरे कराधान के परिहर्तन करने के लिए और आय पर करों की बाबत राज विनीय, अपवंचन के निवारण के लिए एक कन्वेंशन हुआ है;

और भारत और जाम्बिया में वे सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं जो उक्त कन्वेंशन को क्रमशः भारत और जाम्बिया में विधि का बल देने के लिए आवश्यक हैं, और जो उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 के पैरा 1 द्वारा अपेक्षित हैं।

और उक्त दोनों सरकारों के बीच इस आशय के राजनयिक प्रपत्रों का आदान प्रदान हुआ है, जो उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैरा 2 द्वारा अपेक्षित हैं;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

जाम्बिया गणराज्य की सरकार

के बीच,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

अभिसमय,

भारत गणराज्य की सरकार और

जाम्बिया गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय संपन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखी बातों पर सहमत हुई हैं:

अध्याय-1]

अभिसमय का क्षेत्र

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक क्षेत्र विस्तार

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संबन्धकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

अधिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह अधिसमय लागू होगा वे इस प्रकार हैं :

(क) भारत के मामले में :

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत लगाया जाने वाला आयकर जिसमें उस पर लगाया जाने वाला प्रत्येक अधिभार भी शामिल है; और
- (ii) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अंतर्गत लगाया जाने वाला अतिकर।
(जिसका इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में उल्लेख किया जाएगा)

(ख) जांबिया के मामले में :

- (i) आयकर
- (ii) बटिज कर और
- (iii) वैयक्तिक उगाही।

(जिसका इसके बाद 'जांबिया के कर' के रूप में उल्लेख किया जाएगा)।

2. यह अधिसमय किसी समय रूप अथवा साक्ष्य इसी तरह के छद्म रूपों पर भी लागू होगा जो वर्तमान अधिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात् इस अनुच्छेद के पैरा-1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये जाते हों।

3. प्रत्येक वर्ष के अंत में, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, उनके अपने अपने कराधान कानूनों में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हों अधिसमय के विषय हैं उनके संबंध में एक दूसरे को गे और संगत अधिनियमों और विनियमों की प्रतियां भेजेंगे।

अध्याय-II

परिभाषाएं]

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

समय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

5 संविदाकारी राज्य' और 'दूसरे संविदाकारी राज्य' पदबंध संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारत अथवा जांबिया अभिप्रेत

- (ब) 'कर' शब्द से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा जांबिया का कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी एक अथवा भूस के संदर्भ देय हो जिन पर यह अधिसमय लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हो।
- (ज) 'व्यक्ति' शब्द में व्यक्ति, कंपनी और ऐसी सभी अन्य इकाइयां सम्मिलित हैं, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य इकाइयां मानी जाती हैं;
- (ख) 'कंपनी' शब्द से कोई ऐसा निमित्त निकाय अथवा कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्य में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में मानी जाती है;
- (ग) 'एक संविदाकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम' पदबंध क्रमशः संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है;

(ब) भारत के मामले में 'सक्षम प्राधिकारी' पदबंध से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) और जांबिया के मामले में कर आयुक्त अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ख) 'राष्ट्रिक' पद से अभिप्राय है :

(i) भारत के संबंध में,

सभी व्यक्ति जो भारत की राष्ट्रीयता धारण किए हुए हों और ऐसे सभी विधिक व्यक्ति, सहभागी और संगठन जो अपनी हैसियत भारत में लागू कानून से प्राप्त करते हों;

(ii) जांबिया के संबंध में :

सभी व्यक्ति जो जांबिया की राष्ट्रीयता धारण किए हुए हों और ऐसे सभी विधिक व्यक्ति, सहभागी और संगठन जो इस प्रकार अपनी हैसियत जांबिया में लागू कानून से प्राप्त करते हों।

2. किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस अधिसमय के उपबंधों के प्रवर्तन में, किसी भी पद का जो यहाँ अन्यथा परिभाषित नहीं हो, संदर्भ की अन्वया अपेक्षा होने पर, वही अर्थ होगा जो उस राज्य में लागू कर कानूनों के अंतर्गत होता हो जो इस अधिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद - 4

आर्थिक अधिवास

1. इस अधिसमय के द्वोजनों के लिए 'किसी संविदाकारी राज्य का निवासी' पदबंध से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रवृत्ति के स्थान अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य मानक के कारण वहाँ पर कर लगने योग्य हैं।

2. जहाँ पैराग्राफ-1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति में इस अधिसमय के प्रयोजनों के लिए उसके निवास की हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी :

- (क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसका स्थायी निवास गृह हो। यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह हों तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिस राज्य के साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध अनिवार्य रूप से हैं (जिसका उल्लेख इसके बाद उसके 'महत्वपूर्ण हितों के केन्द्र' के रूप में किया जाएगा।
- (ख) अगर उस संविदाकारी राज्य का जो उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, उसका निर्णय न किया जा सकता हो अथवा उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास-गृह हो नहीं हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ वह साधारणतया रहता है;
- (ग) यदि उसका व्यावहारिक आवास संविदाकारी दोनों राज्यों में है अथवा इनमें से किसी भी राज्य में नहीं है तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;
- (घ) यदि वह संविदाकारी दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उन में से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ-1 के उपबन्धों के कारण संविदाकारी दोनों राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है।

अनुच्छेद—5

स्थायी स्थापन

1. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, 'स्थायी स्थापन' पदबंध से कारोबार का वह निम्नलिखित स्थान अभिप्रेत है, जिसमें उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. 'स्थायी स्थापन' पदबन्ध में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- (क) प्रबन्ध का स्थान;
- (ख) शाखा;
- (ग) कार्यालय;
- (घ) कारखाना;
- (ङ) कार्यशाला;
- (च) खान, खदान, निच-खेन अथवा प्राकृतिक साधनों के निष्कर्षण का अल्प स्थान;
- (छ) फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, बनविज्ञान, बाग-बानी अथवा तत्सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं;
- (ज) भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजना परियोजना अथवा उनसे सम्बन्धित पर्यवेक्षी कार्य, जहाँ इस प्रकार का स्थल, परियोजना पर्यवेक्षी कार्य 9 मास से अधिक की अवधि के लिए चालू रहते हों;
- (स) जिस उद्यम से आहरे की पूर्ति की जाती है उसके मास अथवा पथ्यों के भण्डार के रखरखाव के लिए गोदम अथवा अन्य सुविधाएँ।

3. 'स्थायी स्थापन' पदबन्ध में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा:

- (क) उद्यम के मास अथवा पथ्यों के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) उद्यम के मास अथवा पथ्यों के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ स्टॉक रखना;
- (ग) अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित करने के प्रयोजनार्थ उद्यम के मास अथवा पथ्यों का स्टॉक रखना;
- (घ) उद्यम के लिए मास अथवा पथ्यों का केवल ऋण धरने अथवा सूचना संग्रह के प्रयोजनार्थ कारोबार का नियत स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के व्यापार अथवा कारोबार में केवल विज्ञापन देने, सूचना देने, अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के प्रयोजनार्थ, जो अन्य रूप से प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के कार्य हों, के लिए कारोबार का नियत स्थान रखना।

4. अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति—जो स्वतंत्र हैसियत से अधिकर्ता से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ—6 लागू होता हो—प्रथमोक्त राज्य में उस उद्यम की स्थायी स्थापन माना जाएगा, यदि:

- (i) वह उस राज्य में उस उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से संविदा करने का प्राधिकार रखता है और उसका साधारणतः प्रयोग करता है, जब तक उसके विद्या कलाप उस उद्यम के लिए मास अथवा पथ्यों के त्रय तक ही सीमित न हो अथवा
- (ii) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है परन्तु वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में उस उद्यम के मास अथवा पथ्यों का ऐसा स्टॉक साधारणतः रखता है, जिसमें से वह उस उद्यम की ओर से नियमित रूप से मास अथवा पथ्यों की पहुँचता है।

5. किसी संविदाकारी राज्य का कोई भीमा उद्यम केवल पुनः बीमा संबंधी कारोबार को छोड़कर, अन्य संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में स्थायी स्थापना माना जाएगा जब वह किसी कर्मचारी के द्वारा अथवा किसी ऐसे प्रतिनिधि के द्वारा जो पैराग्राफ—6 के अन्तर्गत स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं हो, उस अन्य राज्य की सीमा में बीमा किस्त वसूल करता हो अथवा उसमें स्थित जॉखिम का बीमा करता हो।

6. किसी संविदाकारी राज्य का उद्यम किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से स्थायी स्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी इलाक़, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतन्त्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। किन्तु जब इस प्रकार के एजेंट के कार्यालय उस उद्यम की ओर से पूर्णरूप से अथवा लगभग पूर्णरूप से किए जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अन्तर्गत स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जाएगा।

7. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो संविदाकारी राज्यों में से एक की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः उस दूसरी कम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं बन जाएगी।

8. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का अन्य संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में स्थायी स्थापन माना जाएगा जहाँ वह कोई ऐसा कारोबार करता तो जिसमें उस अन्य संविदाकारी राज्य में लोक-मनोरंजनकर्ताओं (जैसे कि थियटर, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार और संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों की सेवाओं की व्यवस्था करना शामिल हो, जब तक कि ऐसे उद्यम को प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, इस प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने के संबंध में प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य की सरकार की लोक-निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः सहायता नहीं प्राप्त होती हो।

प्रध्याय-III

आय का करधान

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्ति से आय

1. अचल सम्पत्ति से आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिस में ऐसी सम्पत्ति स्थित हो।

2. 'अचल सम्पत्ति' पदबंध की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि और प्रथा के अनुसार की जायेगी जिस में संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पदबंध में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपसाधन रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन-संपत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोड़ने के अधिकार, और खनिज भण्डार, तेलकूप, खदान और प्राकृतिक साधनों के निष्कर्षण के अन्य स्थानों के संवाहन अथवा काम करने के अधिकार के प्रतिफल, के रूप में परिचालनीय अथवा नियत प्रदायगियों के अधिकार। पोल, नौकाएँ और विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे।

3. पैराग्राफ-1 के उपबंध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ-1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल संपत्ति से होने वाली आय और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7**कारोबार से लाभ**

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होंगे, जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार न चलाता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार में लगा हुआ है, तो उद्यम के लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु केवल उतने ही लाभों पर जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं।

2. यदि किसी संविदाकारी राज्य का उद्यम, जिसका अन्य संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन है, समरूप अथवा उसी प्रकार का माल अथवा पण्य बेचता है जैसे कि स्थायी स्थापन द्वारा बेचे जाते हैं, अथवा समरूप या उसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसी कि स्थायी स्थापन द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार के क्रिया-कलापों से प्राप्त लाभों को स्थायी स्थापन के कारण हुए माना जा सकता है, जब तक कि उद्यम यह सिद्ध न कर वे कि इस प्रकार का विपक्ष अथवा सेवाएं स्थायी स्थापन के क्रियाकलाप के कारण नहीं हुई हैं।

3. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहाँ स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापन के कारण उसको उन लाभों का होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती है जब वह उन्हीं अथवा वैसे ही परिस्थिति के अधीन, उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित तथा अलग उद्यम होता और जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णतः स्वतंत्र आधार पर व्यवहार करता होता। किसी भी अवस्था में, जहाँ स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों की सही रकम निर्धारित न की जा सकती हो अथवा उसको निर्धारित करना बहुत ही कठिन हो, वहाँ स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों का अनुमान उपयुक्त आधार पर लगाया जा सकता है।

4. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों के उस के विभिन्न हिस्सों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहाँ पैराग्राफ-3 की कोई भी व्यवस्था उस संविदाकारी राज्य को ऐसी यथा-रुद्धि प्रभाजन पद्धति से, कर लगने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी; तथापि अपनाई गई प्रभाजन-पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

5. किसी स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों की कटौतियाँ की स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यपालीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों परन्तु इसमें ऐसा कोई खर्च शामिल नहीं है, जो उस राज्य के कानून के अंतर्गत, उस राज्य के किसी उद्यम द्वारा कटौती करने के लिए जिसकी अनुमति नहीं हो।

6. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी स्थापन ने, उस उद्यम को निर्यात करने के प्रयोजन से माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है।

7. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्षावर्ष निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण न हो।

8. 'कारोबार से लाभ' पदबंध से किसी उद्यम द्वारा व्यापार अथवा कारोबार करने से प्राप्त होने वाली आय अभिप्रेत है; किन्तु इसमें किराये, रायल्टियाँ (जिनमें दूरदर्शन के लिए सिनेमाटोग्राफिक फिल्में अथवा बीडियो टेप्स में संबंधित किराया अथवा रायल्टियाँ शामिल हैं)। तकनीकी सेवाओं की फीस, प्रबंध-प्रभार, अथवा तकनीकी या अन्य कामिक सेवाएं मुहैया करने के लिए पारिश्रमिक अथवा फीस, ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ, धर्मिक अथवा वैयक्तिक सेवाओं (जिनमें व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं) का पारिश्रमिक अथवा अलपानों अथवा वायुयान के परिचालन से प्राप्त आय शामिल नहीं है।

अनुच्छेद-8**विमान परिवहन**

1. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से प्राप्त लाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 के उपबंध, लाभों के उस श्रेण पर भी लागू होंगे जो किसी संयुक्त विमान परिवहन संचालन व्यवस्था अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में एकीकृत सेवा में भाग लेने से किसी संविदाकारी राज्य के एक उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ-1 के प्रयोजन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान-संचालन से सम्बन्ध निधियों पर ब्याज इस प्रकार के विमान-संचालन से आय माना जाएगा और इस प्रकार के ब्याज के सम्बन्ध में अनुच्छेद-II के उपबंध लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद-9**सम्बन्ध उद्यम**

जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हैं, जो वैसे शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और वे अनुमान कराधेय हो सकेंगे।

अनुच्छेद-10**लाभांश**

1. जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी का श्रदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय हो सकते हैं।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिसकी वह लाभांश देने वाली कंपनी निवासी है, परन्तु इस प्रकार लगाया गया कर नीचे बताई गई रकम से अधिक नहीं होगा:

(क) लाभार्थी की सकल रकम का 5 प्रतिशत, यदि प्राप्तकर्ता कोई ऐसी कंपनी है जो लाभार्थी की भ्रवायगी की सारीख से तत्काल पूर्ववर्ती छः मास की अवधि के दौरान लाभार्थी अदा करने वाली कंपनी के शेयरों के कम से कम 25 प्रतिशत शेयरों का स्वामित्व रखती हो,

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभार्थी की सकल रकम का 15 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'लाभार्थी' पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों, जो ऋण-दावे न हों, लाभों में भागीदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त वह आय है जो शेयरों अथवा किसी ऐसी अन्य मद से प्राप्त आय में समाहित हो, जो उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून द्वारा किसी कंपनी का लाभार्थी अथवा वितरण माना जाता है जिसमें वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ-1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभार्थी प्राप्त करने वाला, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभार्थी अदा करने वाली कंपनी एक निवासी हो, ऐसा स्थायी स्थापन हो, जिससे वह शेयर-धारिता, जिसके कारण लाभार्थी की भ्रवायगी की जाती है, प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद-7 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ कंपनी द्वारा उन व्यक्तियों को लिए गए लाभार्थी पर जो इस दूसरे राज्य के निवासी नहीं हैं; उस दूसरे राज्य में कोई कर नहीं लगाया जाएगा अथवा कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ-कर की किस्म का कोई कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे दिया गया लाभार्थी अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा इतना: उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हो।

अनुच्छेद-11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में यह अर्जित होता है, किन्तु इस प्रकार प्रभारित कर की रकम व्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ-2 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण को उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सेण्ट्रल बैंक अथवा उस सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण की स्वामित्व वाली किसी एजेंसी को प्रदान व्याज पर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य के कर से छूट दी जाएगी। संविदाकारी राज्यों के सभ्य प्राधिकारी; परस्पर सहमति से, किसी भी अन्य सरकारी संस्थान को निर्धारित कर सकत हैं जिस पर यह पैराग्राफ लागू होता हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'व्याज' पद से, सरकारी प्रतिभूतियों, बन्धनपत्रों अथवा ऋण-पत्रों, चाहे वे बंधन द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उनके लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और हर प्रकार के ऋण-पत्रों से प्राप्त आय और साथ ही सभी अन्य ऐसी आय से अभिप्राय है, जो जिस संविदाकारी राज्य में आय उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार, उधार दिए गए धन में

प्राप्त आय में समाविष्ट की गयी हो।

5. पैराग्राफ-1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज प्राप्तकर्ता संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करता हो; और जिस दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह उस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद-7 के उपबंध लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मण्डल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में उसका एक स्थायी प्रतिष्ठान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की भ्रवायगी की गई है; और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा बहन किया जाता है, तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

7. जहाँ व्याज अदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच, अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, अदा की गई व्याज की रकम; उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के सम्बन्ध न होने की स्थिति में अदा करने वाला और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे ऐसे मामले में भ्रवायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

रायल्टियाँ

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसमें वे उद्भूत होती हैं, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'रायल्टियाँ' पद से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों (जिसमें चलचित्र-फिल्में तथा रेडियो अथवा दूर-दर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेप शामिल हैं), कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की भ्रवायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ-1 तथा 2 के उपबंध उस हाल में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टी प्राप्तकर्ता, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ उद्भूत होती हैं वहाँ पर स्थित स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता है जिससे अधिकार अथवा संपत्ति के कारण रायल्टियाँ कारगर रूप से संबंधित हैं। ऐसे मामले में अनुच्छेद-7 के उपबंध लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ उद्भूत हुई मानी जायेंगी यदि गवर्नरी अथवा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उपमण्डल; कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो, परन्तु जहाँ रायल्टियाँ अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में रायल्टी अदा की गई थी और इस प्रकार की रायल्टियाँ उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उद्भूत हुई हैं, तब ऐसी रायल्टियाँ उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी, जिनमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहाँ; रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे हस्तान्तरण, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए वे रायल्टियाँ अदा की जाती हैं, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, अदायगियों के अधिभाग पर, इस प्रकार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-13

पूँजीगत अभिलाष

1. प्रथम संपत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाष, अनुच्छेद-6 के पैराग्राफ-2 में यथापरिभाषित, उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. ऐसी सब संपत्ति के अन्तरण से, जो उस स्थायी प्रतिष्ठान की व्यापारिक संपत्ति का एक भाग हो जो (प्रतिष्ठान) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का अन्य संविदाकारी राज्य में स्थित हो, अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य के व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी निश्चित आधार से संबंधित सब संपत्ति से प्राप्त अभिलाषों पर, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अर्थात् अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निर्धारित स्थान के अन्तरण से प्राप्त अभिलाष भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैराग्राफ-2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा ऐसे जल-पोतों तथा वायुयान के अन्तरण से जिनमें ऐसा उद्यम अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के अंतर्गत परिचालन करता है तथा इस प्रकार के जलपोतों तथा वायुयानों के संचालन से संबंधित सब संपत्ति से प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे।

4. संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित संपत्ति से निम्न किसी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाष केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

5. 'अन्तरण' पद का अर्थ संपत्ति का विक्रय, बिलियम, अन्तरण अथवा त्याग अथवा उनमें किसी भी अधिकार की समाप्ति अथवा अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रयुक्त किसी भी कानून के अंतर्गत उसका अनिवार्य अधिग्रहण है।

अनुच्छेद-14

प्रबन्ध व्यवस्था तथा परामर्श संबंधी फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गई प्रबंध-व्यवस्था तथा परामर्श संबंधी फीस पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की फीस पर कर, उस संविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होती हैं, किन्तु इस प्रकार लगाए गए कर की रकम फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त 'प्रबंध और परामर्श संबंधी फीस' पद बंध का अर्थ, अदायगी करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी से अथवा अन्य व्यक्तियों को प्रबन्धकीय तकनीकी अथवा परामर्शों किस्म की किन्हीं सेवाओं के प्रतिफल के रूप में की जाने वाली किसी भी प्रकार की अदायगी है।

4. पैराग्राफ-1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब प्रबन्ध और परामर्श संबंधी फीस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते उस दूसरे संविदाकारी राज्य में जिनमें फीस उद्भूत होती है, कोई ऐसा स्थायी प्रतिष्ठान हो जिससे वे सेवाएँ, कारणरूप से सम्बन्ध हों जिनके कारण फीस उद्भूत होती हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद-7 के उपबंध लागू होंगे।

5. प्रबन्ध और परामर्श संबंधी फीस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई तब मानी जाएगी जबकि अथवा करने वाला, स्वयं वह संविदाकारी राज्य हो, कोई राजनीतिक उपमण्डल हो, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ प्रबन्ध और परामर्श संबंधी फीस अदा करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह उस राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में फीस अदा की गयी हो और ऐसी फीस इस प्रकार के प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाती है ता ऐसी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायती जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहाँ अदा करने वाले तथा प्राप्त करने वाले के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष सम्बन्ध होने के कारण प्रबन्ध तथा परामर्श सम्बन्धी फीस की अदा की गई रकम उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए फीस की अदायगी की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके बारे में इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाला तथा प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसी स्थिति में, अदा की गई रकमों के अधिक भाग पर, इस प्रकार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-15

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ

1. अनुच्छेद-16 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, व्यक्ति-संबंधी सेवाओं अथवा इसा प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि—

(क) अपने कार्य-कलापों के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध न हो, जिस मामले में उस दूसरे राज्य में कर उतनी रकम पर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो; अथवा

(ख) भारत के मामले में वह संगत 'पूर्ववर्ती वर्ष' में तथा जाम्बिया के मामले में संगत 'कर-प्रकार' में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अधिकांशों के लिए अपने कार्य-कलापों के प्रयोजन के निमित्त, दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित नहीं रहा हो और ऐसी स्थिति में उस राज्य में आय की

उत्तरी एकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में किये गये कार्य-कलापों के कारण उत्पन्न हुई मानी जा सकती हो।

- (ग) दूसरे संविदाकारी राज्य में उम्र उस संविदाकारी राज्य के निवासियों से अपनी सेवाओं और कार्य-कलापों के लिए प्राप्त पारिश्रमिक की एकम, इसके बावजूद कि उस राज्य में कराधेय वर्ष के दौरान उसके निवास की अवधि अथवा अवधियों का कुल योग 183 दिन से कम हो, कराधेय वर्ष में 10,000 रुबाया अथवा भारतीय मुद्रा में उसके समतुल्य एकम (जिसमें दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई सेवाओं अथवा कार्य-कलापों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित यासां-अथ यासिन नहीं है) से अधिक नहीं हों।

2. 'बुलि संबंधी सेवाएं' पदबंध में स्वतंत्र वैज्ञानिक, सांख्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्य-कलापों तथा चिकित्सकों, बकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दैन-विकिन्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप की शामिल हैं।

अनुच्छेद-16

परमजिन वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद-17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासियों को, नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन, सज्जरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि उनका नियोजन दूसरे सम्बन्ध संविदाकारी राज्य में न हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उनसे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ-1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयुक्त नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रथमोक्त राज्य में ही लगेगा यदि—

- (क) प्राप्तकर्ता आय के वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद रहा है, और
- (ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसको जोर से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्वामी प्रतिष्ठान अथवा निविजन स्थान द्वारा बहिन न किया गया हो, जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. पैराग्राफ-1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जखपों पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उन उद्यम को प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था है।

अनुच्छेद-17

निर्देशक-मुक्त

संविदाकारी राज्य निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य का अमियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निर्देशक का फौज दमा इसी प्रकार को अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद-18

कलाकार और खिलाड़ी

अनुच्छेद-15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक-मनोरंजन-कर्त्ताओं (जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूर-दर्शन कलाकार तथा मंचोत्पादक) अथवा खिलाड़ियों को अपनी हैसियत से अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किये गए हों।

किन्तु ऐसा काम पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लग सकेगा, यदि लोक-मनोरंजनकर्त्ताओं अथवा खिलाड़ियों को उस राज्य की यात्रा का, व्यय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार का सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, 'सरकार' पद में दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की राज्य सरकार, राजनैतिक उप-मण्डल, अथवा स्थानीय अथवा सांख्यिक प्राधिकारी सम्मिलित माने जाएंगे।

अनुच्छेद-19

सरकारी कार्य

1. किसी संविदाकारी राज्य, राजनैतिक उप-मण्डल, अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य के किसी नागरिक को किसी नियोजन के संबंध में अदा किए गए अथवा सृजित की गई निधियों में से दिये गये पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में ही लगेगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य, राजनैतिक उप-मण्डल, अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति को अथवा को गई अथवा सृजित की गई निधियों में से दो गई किसी भी पेशान पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा, लाभ के प्रयोजन, रखे जा रहे किसी व्य.पर के संबंध में की गई सेवाओं के लिए अदा की गई रकमों पर लागू नहीं होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए सरकार पद में दोनों संविदाकारी राज्यों को कोई भी राज्य सरकार अथवा स्थानीय अथवा सांख्यिक प्राधिकारी और विशेषरूप से, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नक आण्ड आम्बिया शामिल होंगे।

अनुच्छेद-20

गैर सरकारी पेशान तथा व्यक्तिगत

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासियों द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के लोगों से प्राप्त कां. जा. रहों किसी भी पेशान (अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेशान से भिन्न) अथवा व्यक्ति पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकता है।

2. 'पेशान' पद का अर्थ उस नियतकालिक मुगलान से है जो विगत समय में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक श्रम को क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो।

3. 'व्यक्ति' पद का अर्थ उस उल्लिखित पेशान से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिए, अदायगियां करने के किसी व्यक्ति के अधीन, जीवन पर्यंत अथवा विनिश्चित अथवा निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होंगे।

अनुच्छेद-21

अनुसंधान कामिक, विद्यार्थी तथा व्यापार प्रशिक्ष

1 (क) कोई व्यक्ति जो उस समय संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो वह दूसरे संविदाकारी राज्य के इस मूल प्रयोजन के लिए अर्थात्—

- (i) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यता-प्राप्त संस्थान में अध्ययन के लिए,
- (ii) व्यवसाय चलाने अथवा व्यवसाय संबंधी विशेषज्ञता का उपयोग करने के बारे में अज्ञान प्राप्त करने के निमित्त अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, अथवा
- (iii) सरकारी धार्मिक धर्मार्थ, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा शैक्षिक संगठन से अनुदान, भत्ता, अथवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में अध्ययन करने अथवा अनुसंधान कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से मौजूब हो, उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उप-पैराग्राफ (ख) में उल्लिखित रकमों के संबंध में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से उस अधि के लिए जो कर लगने योग्य 5 वर्ष से अधिक नहीं हो, कर से छूट दी जाएगी।

(ख) उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित रकमों हैं :-

- (i) अपने भरण-पोषण, शैक्षिक अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिये विदेश में प्राप्त दान;
- (ii) अनुदान भत्ता, अथवा पुरस्कार, और
- (iii) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई सेवाओं से प्राप्त आय जो किसी भी कर योग्य वर्ष के संबंध में 1,500 जाम्बियाई क्वाचा अथवा उसके समतुल्य भारतीय रुपये से अधिक नहीं हो।

2. एक व्यक्ति जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी हो और जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोजित संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के एक कर्मचारी के रूप में अथवा ठेके के अंतर्गत एक कर्मचारी के रूप में—

- (क) प्रयोजित संविदाकारी राज्य के उस निवासी से भिन्न किसी व्यक्ति से अथवा ऐसे निवासी से संबंधित किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से तकनीकी व्यावसायिक, अथवा व्यापार संबंधी अनुभव करने, अथवा
- (ख) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था में अध्ययन करने के मुख्य प्रयोजन के लिए अस्थायी तौर से उपस्थित रहता है उसे, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी वैयक्तिक सेवाओं से प्राप्त आय पर, जिसकी कुल रकम 2,500 जाम्बियाई क्वाचा अथवा उसके समतुल्य भारतीय रुपयों से अधिक नहीं हो, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी।

3. एक व्यक्ति को जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम में एक भागीदार के रूप में, प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा अध्ययन के मुख्य प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, इस तरह के प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा अध्ययन के संबंध में का गई वैयक्तिक सेवाओं से प्राप्त आय पर, जो 3,500 जाम्बियाई क्वाचा अथवा इसके समतुल्य भारतीय रुपये से अधिक नहीं हो, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद-22

प्राध्यापक और अध्यापक

1. एक प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो प्रयोजित राज्य में अधिक से अधिक दो वर्षों की अवधि के लिए, उच्च अध्ययन प्रवृत्ति कार्य करने के प्रयोजनार्थ अथवा किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्कूल अथवा अन्य शैक्षिक संस्था में अध्यापन करने के लिए, प्रयोजित राज्य में ऐसे किसी पारिश्रमिक के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी जिसे वह इस प्रकार के कार्य के लिए प्राप्त करता है, बशर्ते कि उसके द्वारा ऐसा पारिश्रमिक उस राज्य के बाहर से प्राप्त किया जाता है।

2. यह अनुच्छेद अनुसंधान कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मुख्य रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभों के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद-21 के उद्देश्यों के लिए कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस संविदाकारी राज्य में 'पूर्ववर्ती वर्ष' में अथवा 'कर प्रभार वर्ष' में जैसी भी स्थिति हो, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा तुरन्त पहले के 'पूर्ववर्ती वर्ष' अथवा 'कर-प्रभार वर्ष' में निवासी है।

अनुच्छेद-23

आय, जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मध्य में जहाँ कहीं भी उद्भूत होती हो और जिनका इस अधिसूचना के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवेचन नहीं किया गया है, वे केवल उस राज्य में कर लगने योग्य होंगी, सिवाय इसके कि यदि ऐसी आय दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है तो उस पर दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

अध्याय IV

दोहरे कराधान के उपकरण के लिए प्रणाली

अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का परिहार

1. इस अधिसूचना में बनाए गये विपरीत प्रावधानों को छोड़कर दोनों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को शासित करते रहेंगे।

2. (क) जाम्बिया के कानूनों के अंतर्गत और इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्यक्षः अथवा कटौती द्वारा भारत के किसी निवासी की जाम्बिया में स्थित साधनों से प्राप्त आय पर भारत और जाम्बिया दोनों में कर लगाया गया है, तो देय जाम्बिया के कर की रकम को, उक्त आय के संबंध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायगी, बशर्ते कि ऐसी जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व यथासंगणित) भारतीय कर की उक्त रकम से अधिक नहीं हो, जो जाम्बिया में स्थित साधनों से प्राप्त आय के अनुरूप हो, लेकिन जहाँ ऐसा निवासी एक ऐसी कंपनी है जिसे भारत में अतिकर अया करना है, वहाँ उपर्युक्त जमा रकम प्रथम बार कम्पनी द्वारा भारत में आयकर के प्रति देय मानी जाएगी, और शेष रकम यदि कोई हो तो वह उसके द्वारा भारत में अया किये जाने वाले अतिकर के रूप में जमा मानी जायगी।

(ख) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिए, 'जाम्बिया का देय कर' पदबन्ध में ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए जाम्बिया के कर के रूप में देय रही हो, परन्तु ऐसे किसी उपबन्धों को छोड़कर, जो आर्थिक विकास जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हों।

3 (क) भारत के राज्यों के अन्तर्गत और उच्च यन्त्रिमय के उपबन्धों के अनुसार, पर्यवेक्षण अथवा कटौती द्वारा जाम्बिया के किसी निवासी की भारत में स्थित साधनों से प्राप्त आय पर भारत और जाम्बिया दोनों में कर लगाया गया है, तो देय भारतीय कर की रकम को, उक्त आय के संबंध में देय जाम्बिया के कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायेगी बशर्ते कि जमा की रकम (ऐसी जमा स्वीकृत किये जाने से पूर्व यथासंगणित) जाम्बिया के कर की उस रकम में अधिक नहीं हो, जो भारत में स्थित साधनों से प्राप्त आय के अनुरूप है ;

(ख) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिए 'देय भारतीय कर' पत्रबंध में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गई मान ली जायेगी जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की निम्नलिखित धाराओं में निर्धारित किए गये विशेष प्रोत्साहन उपायों के अनुसार भारतीय कर घटा दिया गया है।—

- (i) धारा 10(1) जो किसी अनिवासी को, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्रतिभूति पर देय व्याज पर कर से छूट के सम्बन्ध में है ;
- (ii) धारा 10(4क)—जो अनिवासी (परराष्ट्रीयक) लेखों की रकमों पर किसी अनिवासी को देय व्याज पर कर से छूट के बारे में है ;
- (iii) धारा 10(15) (iv)—जिसका संबंध निम्नलिखित को कर से छूट देने से है : (क) किसी अनिवासी द्वारा भारत सरकार अथवा वहां के स्थानीय प्राधिकरण को उधार दिये गये धन के सम्बन्ध में उसे छूट ; (ख) किसी स्वीकृत विदेशी वित्तीय संस्था द्वारा भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम की किसी कण-करण के अन्तर्गत उधार दिये गये धन पर व्याज ; और (ग) किसी अनिवासी द्वारा भारत में किसी औद्योगिक उपक्रम को भारत में वाहर कच्चे माल अथवा पूंजी के रूप में संचयन तथा मशीनरी अथवा औद्योगिक विकास के लिए उधार दिये गये धन अथवा उधार सुविधाओं पर व्याज ;
- (iv) धारा 32क—जो जलपोतों, वायुयानों, मशीनरी अथवा संचयन के सम्बन्ध में निवेश में छूट के बारे में है ;
- (v) धारा 33क—जो ताय के रोपण के रोपण और पुनः रोपण के लिए विकास छूट के बारे में है ;
- (vi) धारा 35ग—जो कृषि विकास छूट के संबंध में है ;
- (vii) धारा 54इ—जो पूंजीगत लाभों के बारे में है ;
- (viii) धारा 80गग—जो कुछ नये शेषों के सम्बन्ध में कटौती के बारे में है ;
- (ix) धारा 80अज—जो कृषिपथ क्षेत्रों में नव-स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाषों के संबंध में कटौती के बारे में है ;
- (x) धारा 80अ—जो उपयुक्त औद्योगिक उपक्रमों अथवा जलपोतों अथवा होटलों से लाभों और अभिलाषों के संबंध में कटौती के बारे में है ;
- (xi) धारा 80ट—जो उपयुक्त औद्योगिक उपक्रमों अथवा जलपोतों अथवा होटलों से लाभों और अभिलाषों के कारण देय लाभभागों के संबंध में कटौती के संबंध में है ;
- (xii) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर की छूट अथवा कमी प्रदान करने के लिए बाद में अधिनियमित किये जायें, जिनके बारे में दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच यह सहमति हो कि वे आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए हैं ।

1 इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार जिस आय पर एक संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता है, उसे, उस संविदाकारी राज्य में लगाये जाने वाले कर की दर को संगणना के लिए हिसाब में लिया जा सकेगा ।

अध्याय-V

विषय उपबन्ध

अनुच्छेद-25

सम-उपबन्ध

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के स्थायी संस्थान पर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में है, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जायेगा जो उस दूसरे राज्य के, वैसी ही परिस्थितियों में वैसी ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो ।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि इसमें एक संविदाकारी राज्य को, ऐसे व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनों के लिये किसी भी प्रकार की वैयक्तिक छूट, राहतें और घटौतियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कानूनन केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जो वहां के निवासी हैं ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा शपथकृतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं, प्रयोजित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसी कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रयोजित राज्य के अन्य वैसी ही उद्यमों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू है अथवा हो सकती हैं ।

5. इस अनुच्छेद में 'कराधान' पद का अर्थ उन करों से है, जो इस अभिसमय का विषय हैं ।

अनुच्छेद-26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण कराधान लगाया जाता है अथवा लगाया जायेगा, जो इस अभिसमय के अनुकूल नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का निवासी है, अपना मामला उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला उस कार्यवाही के नोटिस को प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिससे ऐसे कराधान में वृद्धि होती है जो अभिसमय के अनुसार नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपर्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल कर का प्रयास करेगा। सम्पन्न किये गये किसी भी करार को कार्यान्वित किया जाएगा, चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो ।

८. इस प्रकार की सलाह देने परका इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाईया अथवा जो उपर्युक्तों को संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। ये उन मामलों में दोहरा कराधान के अपाकरण के लिए एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी अभिसमय में व्यवस्था नहीं है।

९. पूर्वी का वैरी के अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सहमत होने में जब वित्तों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किये जा सकते हैं जिसमें संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद-27

सूचना का आदान-प्रदान

१. संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारों ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज का आदान-प्रदान करेंगे जो इस प्रकार के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उन बरों के अपवर्जन को रोकने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के विषय है। इस प्रकार आदान-प्रदान की गयी सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जायेगा, लेकिन उसे ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारों शामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा, जो उन बरों को निर्धारण वसूला पवर्जन, जांचपट्टाल अथवा अभियोजन से संबंधित हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा, जिनसे सूचना अथवा दस्तावेज का संबंध है।

२. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान तब आधार पर होगा अथवा विशेष मामलों के संबंध में अनुरोध पर किया जा सकेगा, ऐसी आधार पर ही जिन बांधी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची के संबंध में संबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों को समय-समय पर सहमति आवश्यक होगी।

३. किसी भी स्थिति में पैरा-1 के उपबन्धों का वह अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिसमें कि किसी संबिदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार डाला जाय :—

- (क) एक अथवा दूसरे संबिदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा में हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो एक अथवा दूसरे संबिदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा पणायन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिसमें कोई व्यापारिक, व्यवसायिक, औद्योगिक, आर्थिक अथवा राजस्व संबंधी गुप्त और अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसकी प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिष्ठित हो।

अनुच्छेद-28

राजनयिक और कौंसली कार्य

अन्तराष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेषतः करों के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त अभिसमय में राजनयिक अथवा कौंसली अधिकारियों के राज्य-कर विषयक विज्ञेयाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय - 6

उपसंहार

अनुच्छेद - 29

प्रवर्तन

१. यह अभिसमय उस तारीख से लागू होगा जब भारत में तथा जाम्बिया में ये सभी बातें पूरी कर ली जाएंगी जो इस अभिसमय की कमजोर भाग में तथा जाम्बिया में कानून को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।

२. दोनों संबिदाकारी राज्य इस अनुच्छेद के पैरा-1 में उल्लिखित अपेक्षाओं का पूरा हो जाने को एक दूसरे के साथ प्रशिक्षित करेंगे। राजनयिक टिप्पणियों का आदान-प्रदान, जिनमें यह प्रमाणित किया गया हो कि यह अपेक्षा पूरी कर ली गई है, लगातार में किया जाएगा।

३. ऐसी राजनयिक टिप्पणियों का आदान-प्रदान हो जाने पर यह अभिसमय -

(क) भारत में, 1 अप्रैल, 1979 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में कर-निर्धारण योग्य आय के बारे में;

(ख) जाम्बिया में, 1 अप्रैल, 1979 को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी भी कर-प्रकार वर्ष के संबंध में उत्पन्न होने वाली आय के बारे में;

लागू होगा।

अनुच्छेद - 30

समाप्ति

यह अभिसमय अतिशयतः काल तक लागू रहेगा परन्तु कोई भी संबिदाकारी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के समाप्त होने के बाद आरम्भ होने वाली किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून के तीसरे दिन को अथवा उससे पहले दूसरे संबिदाकारी राज्य को, राजनयिक माध्यमों में समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा और वैसी स्थिति में यह अभिसमय :—

(क) जाम्बिया में, जिन कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो उसके अगले परवर्ती दूसरे कैलेंडर वर्ष में और परवर्ती वर्षों में, अप्रैल के प्रथम दिन को शुरू होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में कर-निर्धारण योग्य आय के बारे में;

(ख) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती वर्ष में तथा बाद के वर्षों में आय के वर्ष के संबंध में उत्पन्न होने वाली आय के बारे में;

लागू नहीं रहेगा।

जिसके माध्यम से इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

लुगाका में वर्ष एक हजार तीसरी दशक की जून मास के पांचवें दिन अग्नेयी भाषा की दो प्रतियों में किया गया।

केदार पाण्डे, ज्येष्ठ सचिव,

भारत गणराज्य की सरकार

मानव संसाधन, एम. ए. म्पूकोटेबाने, सहाय सचिव

जिम्बेब्वे, जाम्बिया गणराज्य

की सरकार,

[क्र. सं. 501/11/65/एफ. टी. डी.]

चाह कृपया निम्न, सूचना पत्र

MINISTRY OF FINNCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 18th January, 1984

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 39(E).—Whereas the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Zambia have concluded a Convention as set out in the Annexure hereto, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

And whereas all the requirements have been completed in India and Zambia as are necessary to give the said Convention the force of law in India and Zambia respectively, as required by paragraph 1 of Article 29 of the said Convention ;

And whereas the diplomatic notes to this effect have been exchanged between the said two Governments, as required by paragraph 2 of Article 29 of the said Convention ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

**CONVENTION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
ZAMBIA
FOR**

**THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Zambia.

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Have Agreed as follows :

CHAPTER I

Scope of the Convention

Article I

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Convention shall apply are :

(a) In the case of India :

(i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and

(ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);

(hereinafter referred to as "Indian tax").

(b) In the case of Zambia :

(i) the income tax ;

(ii) the mineral tax ; and

(iii) the personal levy

(hereinafter referred to as "Zambian tax").

2. The Convention shall also apply to any identically similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any changes which have been made in their respective taxation laws which are the subject of this Convention and furnish copies of relevant enactments and regulations.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

(a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Zambia, as the context requires ;

(b) the term "tax" means Indian tax or Zambian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes ;

(c) the term "person" includes individuals, companies and all other entities which are treated as taxable units under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws in force in the respective Contracting State ;

(e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue); and in the case of Zambia, the Commissioner of Taxes or his authorised representative ;

(g) the term "nationals" means :

(i) in respect of India :

all individuals possessing the nationality of India and all legal persons, partnerships and associations deriving their status from the law in force in India;

(ii) in respect of Zambia :

all individuals possessing the nationality of Zambia and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Zambia.

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article-4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Convention shall be determined in accordance with the following rules—

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interest");
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Whereby reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both of Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include :—

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, a quarry, an oil field or other place of extraction of natural resources ;
- (g) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry plantation or related activities are carried on ;
- (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than 9 months ;
- (i) a warehouse or other facilities for the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which orders are filled.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character, in the trade or business of the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply—shall be

deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if :

- (i) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise ; or
- (ii) he has no such authority but the habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to that enterprise from which he regularly fulfils orders on behalf of the enterprise.

5. An insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of independent status within the meaning of paragraph 6.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not, of itself, constitute for either company a permanent establishment of the other.

8. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported wholly or substantially, from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. If an enterprise of a Contracting State, which has a permanent establishment in the other Contracting State, sells goods or merchandise of the same or similar kind as those sold by the permanent establishment or renders services of the same or similar kind as those rendered by the permanent establishment, the profits of such activities may be attributed to the permanent establishment unless the enterprise proves that such sales or services are not attributable to the activity of the permanent establishment.

3. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise

to its various parts, nothing in paragraph 3 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that State, would not be allowed to be deducted by an enterprise of that State.

6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.

7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

8. The term "business profits" means income derived by an enterprise from the carrying on of trade or business; but does not include income in the form of rents, royalties (including rents or royalties in respect of cinematographic films or video tapes for television), fees for technical services, management charges, or remuneration or fees for providing services of technical or other personnel, interest, dividends, capital gains, remuneration for labour or personal (including professional) services or income from the operation of ships or aircraft.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to a share of profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

3. For the purpose of paragraph 1, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State;

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:

- (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends during the period of six months immediately preceding the date of payment of the dividends;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other item which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to

persons who are not residents of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or local Authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State, or any agency wholly owned by that Government or local authority shall be exempt from tax of the first mentioned Contracting State. The competent authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph shall apply.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned

amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne of such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships and aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in that State.

5. The term "alienation" means the sale, exchange, transfer, or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition thereof under any law in force in the respective Contracting States.

Article 14

MANAGEMENT AND CONSULTANCY FEES

1. Management and consultancy fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such fees may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of the State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees.

3. The term "management and consultancy fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial technical or consultancy nature.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the management and consultancy fees, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the fees arise a permanent establishment with which the services giving rise to the fees are effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Management and consultancy fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the fees, whether he is a resident of that State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the fees was incurred and such fees are borne by such permanent establishment, then such fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the management and consultancy fees paid, having regard to the services for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Article 16, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless :

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or
- (b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in relevant "previous year" in the case of India and in the relevant "charge year" in the case of Zambia and in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.
- (c) his remuneration for his services or activities in the other Contracting State derived from residents of that Contracting State exceeds K 10,000 or its equivalent in Indian currency in the taxable year (not including travel expenses directly related to the services or activities in the other Contracting State), notwithstanding that his stay in that State is for a period or periods amounting to less than 183 days during the taxable year.

2. The term "professional services" includes independent scientific literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such representation as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if :

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration in respect of employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised :

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article, the term 'Government' includes a State Government, a political sub-division, or a local or statutory authority of either Contracting State.

Article 19

GOVERNMENTAL FUNCTIONS

1. Remuneration paid by or out of funds created by a Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof, to a citizen of that State in respect of an employment shall be taxable only in that State.

2. Any pension paid by or out of funds created by a Contracting State a political sub-division, or a local authority thereof, to any individual may be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Bank of Zambia.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension (other than a pension referred to in Article 19) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during the life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 21

RESEARCH PERSONNEL, STUDENTS AND BUSINESS APPRENTICES

1. (a) An individual who is a resident of one of the Contracting States at the time he becomes temporarily present in the other Contracting State for the primary purpose of—

- (i) studying at a University or other recognised educational institution in that other Contracting State, or
- (ii) securing training required to qualify him to practise a profession or professional speciality, or
- (iii) studying or doing research as a recipient of a grant allowance, or award from a Governmental religious, charitable, scientific, literary, or educational organisation,

shall be exempt from tax by that other Contracting State with respect to amounts described in sub-paragraph (b) for a period not exceeding 5 taxable years from the date of his arrival in that other Contracting State.

(b) The amounts referred to in sub-paragraph (a) are :—

- (i) gifts abroad for the purpose of his maintenance, educational, study, research, or training ;
- (ii) the grant, allowance, or award ; and

- (iii) income from personal services performed in that other Contracting State in an amount not in excess of 1,500 Zambian Kwacha or its equivalent Indian Rupees for any taxable year.

2. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who is temporarily present in that other Contracting State as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned Contracting State, for the primary purpose of—

- (a) acquiring technical, professional, or business experience from a person other than that resident of the first-mentioned Contracting State or other than a person related to such resident, or
- (b) studying at a University or other recognised educational institution in that other Contracting State, shall be exempt from tax in that other Contracting State for a period not exceeding 1 year with respect to his income from personal services in an aggregate amount not in excess of 2,500 Zambian Kwacha or its equivalent Indian Rupees.

3. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who is temporarily present in that other Contracting State for a period not exceeding 1 year, as a participant in a programme sponsored by the Government of that other Contracting State, for the primary purpose of training, research, or study, shall be exempt from tax in that other Contracting State with respect to his income from personal services in respect of such training, research, or study performed in that other Contracting State in an aggregate amount not in excess of 3,500 Zambian Kwacha or its equivalent Indian Rupees.

Article 22

PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for a period not exceeding two years for the purpose of carrying out advanced study or research or for teaching at a university, college, school or other educational institution shall be exempt from tax in the first-mentioned State in respect of any remuneration which he receives for such work, provided that such remuneration is derived by him from outside that State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "charge year", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "charge year".

Article 23

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State except that if such income arises in the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

CHAPTER IV

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. (a) The amount of Zambian tax payable, under the laws of Zambia and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Zambia which has been subjected to tax both in India and Zambia, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Zambia; so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income-tax payable by the company in India, and as to the balance, if any against surtax payable by it in India;

(b) For the purpose of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, the term "Zambian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Zambian tax for any year but for any provisions granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purpose of economic development.

3. (a) The amount of Indian tax payable, under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Zambia in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Zambia shall be allowed as a credit against Zambian tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed the Zambian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within India;

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which Indian tax has been reduced by the special incentive measures set forth in the following sections of the Income-tax Act, 1961.

- (i) Section 10(4)—relating to exemption from tax on interest payable to a non-resident on any security notified by the Government of India;
- (ii) Section 10(4A)—relating to exemption from tax on interest payable to a non-resident on moneys in a Non-resident (External) Account;
- (iii) Section 10(15)(iv)—relating to exemption from tax of (a) a non-resident in respect of moneys lent by him to the Government or local authority in India; (b) an approved foreign financial institution in respect of interest on moneys lent by it to an industrial undertaking in India under a loan agreement; and (c) a non-resident in respect of interest on moneys lent or credit facilities allowed by him to an industrial undertaking in India for the purchase outside India of raw materials or capital plant and machinery or for industrial development in India;
- (iv) Section 32A—relating to investment allowance in respect of ships, aircrafts, machinery or plant;
- (v) Section 33A—relating to development allowance for planting or replanting of tea bushes;
- (vi) Section 35C—relating to the agricultural development allowance;
- (vii) Section 54E—relating to capital gains;
- (viii) Section 80CC—relating to deduction in respect of investment in certain new shares;
- (ix) Section 80HH—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas;
- (x) Section 80J—relating to deduction in respect of profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels;
- (xi) Section 80K—relating to deduction in respect of dividends attributable to profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels;
- (xii) any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the contracting States agree to be for the purposes of economic development.

4. Income which, in accordance with the provisions of this Convention is not to be subjected to tax in a

Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance

with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the inter-pretation or application of the Convention. They may also consult each other for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of evasion of taxes which are the subject of this Convention. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or other authorities) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Convention, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial,

commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall come into force on the date when the last of all such things shall have been done in India and Zambia as are necessary to give the Convention the force of law in India and Zambia respectively.

2. The Contracting States shall notify each other of the completion of the requirements mentioned in paragraph 1 of this Article. The exchange of diplomatic notes certifying that this requirement has been completed shall take place at Lusaka.

3. Upon the exchange of such diplomatic notes, this Convention shall have effect :

- (a) In India, in respect of income assessable for any assessment year commencing on or after the 1st day of April, 1979.
- (b) In Zambia, in respect of income arising for any charge year commencing on or after the 1st day of April, 1979.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination, and in such event this Convention shall cease to be effective :

- (a) in Zambia, in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years ;

- (b) in India, in respect of income arising for the year of income next following the calendar year in which the notice of termination is given, and subsequent years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present convention.

Done in duplicate at LUSAKA this FIFTH day of JUNE one thousand nine hundred and Eighty one in English language.

Sd/-

HON. S. K. MUSSOKOTWANE, M.P.,
Minister of Finance,
Government of the Republic of Zambia.
[F. No. 11/11/65-FTD]
C. K. TIKKU, Jt. Secy.

Sd/-

KEDAR PANDEY,
Minister of Railways,
Government of the
Republic of India.

